इकाई 1 राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति, विषय क्षेत्र और उपयोगिता

संरचना

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 राजनीति का तुलनात्मक अध्ययनः प्रकृति और विषय -क्षेत्र

1.2.1 तुलनाएँ : संबंधों की पहचान

1.2.2 तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार

1.3 तुलनात्मक राजनीति : एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन

1.3.1 राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उत्पत्ति

1.3.2 उन्नीसवीं सदी का अन्त और बीसवीं सदी का प्रारंभ

1.3.3 द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात्

1.3.4 1970 का दशक और विकासवाद की चुनौतियाँ

1.3.5 1980 का दशक : राज्य की वापसी

1.3.6 बीसवीं सदी का अंत : वैश्वीकरण और उभरती प्रवृत्तियाँ/संभावनाएँ

1.4 राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन : उपयोगिता

1.4.1 सैद्धांतिक सूत्रीकरण के लिए तुलना

1.4.2 वैज्ञानिक कठोरता के लिए तुलनाएँ

1.4.3 तुलनाएँ जो संबंधों में व्याख्याओं की ओर ले जाएँ

1.5 सारांश

1.6 मुख्य शब्द

1.7 संदर्भ

1.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.0 उद्देश्य

हम अक्सर जाने-अनजाने, अपनी तुलना दूसरों से करते हैं ; दूसरे क्या सोचते हैं, वे क्या करते हैं या कैसे जीते हैं इत्यादि। दूसरों के साथ-तुलना और अपने चारों ओर की वस्तुओं की तुलना करना हमें दूसरों के व्यवहार के संदर्भ में अपने खुद के व्यवहार को और गहराई से समझने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार की तुलना की प्रक्रिया काफी हद तक हमारी निजता को रुप देती है। इस प्रकार की तुलना की प्रक्रिया सामूहिक स्तर पर भी घटित होती है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अन्तर्गत, राष्ट्रों के आर-पार विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं, गतिविधियों आदि की तुलना के क्रियाकलाप में हम हिस्सा लेते है।

इस प्रारंभिक इकाई को इस उद्देश्य से बनाया गया कि हम राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में सैद्धांतिक और विधि-तांत्रिक दृष्टि से जानकारी प्राप्त कर सकें। इस इकाई में हम राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के प्रधान

पहलुओं –प्रकृति, विषय क्षेत्र और उपयोगिता – पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित में सक्षम होंगे

- राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के अर्थ और विषय क्षेत्र की व्याख्या
- राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रमुख अवधारणाओं की परिभाषा और वर्णन
- राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य की व्याख्या
- राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व/लाभ और प्रासंगिकता की व्याख्या
- राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि/विकास का वर्णन
- राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन में प्रयोग की जाने वाली मुख्य अवधारणाओं की पहचान और व्याख्या

1.1 प्रस्तावना

राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का संबंध राजनीतिक परिघटनाओं की तुलना से है। तुलनात्मक राजनीति का मूल उद्देश्य विश्व के देशों के बीच मुख्य राजनीतिक समानताओं और भिन्नताओं को सम्मिलित करना है। बल इस बात पर दिया जा रहा है किस प्रकार विभिन्न समाज दूसरों के साथ तुलना के माध्यम से विविध समस्याओं का सामना करते हैं। यद्यपि 'तुलनात्मक पद्धतियाँ' और 'तुलनाओं की विधियाँ' अन्य विषयों में भी व्यापक रुप से प्रयोग की जाती हैं, उदाहरण के लिए, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि, परन्तु तुलनात्मक राजनीति का तत्व है – अर्थात् उसकी विषय -वस्तु, शब्दावली, परिप्रेक्ष्य, और अवधारणाएँ – जो तुलनात्मक राजनीति को दोनों प्रकार से उसकी विशिष्टता प्रदान करता है, एक 'पद्धति' के रुप में भी और 'तुलनात्मक राजनीति' के अध्ययन के एक रुप उप-क्षेत्र के रुप में भी।

तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय -क्षेत्र का ऐतिहासिक दृष्टि से निर्धारण (क) विषय -वस्तु (ख) शब्दावली और (ग) राजनीति परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनों द्वारा हुआ है। ये समझने के लिए कि ये परिवर्तन कहाँ, क्यों और कैसे हुए, हमें ये देखना होगा कि एक निश्चित ऐतिहासिक काल में, अध्ययन का केन्द्र क्या है, अध्ययन के लिए किन उपकरणों, भाषाओं या अवधारणाओं का प्रयोग हो रहा है और अन्वेषण का प्रेक्षण स्थल, परिप्रेक्ष्य और उद्देश्य क्या है। अतः आगामी खंडों में, हम तुलनात्मक राजनीति के विकास के तरीके, इस विकास को अनुप्राणित करने वाली निरंतरताओं और विछिन्नताओं, जिन तरीकों से विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भों में और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बलों द्वारा इस विकास का निर्धारण हुआ है, और किस प्रकार बीसवीं सदी के अन्त के प्रसगं में, अर्थात् वैश्वीकरण के प्रसंग में, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में अब तक किए गए विचारों के तरीके में आमूल परिवर्तन लाए गए हैं, इन सब पर विचार करेंगे।

1.2 राजनीति का तुलनात्मक अध्ययनः प्रकृति और विशय - क्षेत्र

राजनीति का तुलात्मक अध्ययन : प्रकृति और विषय क्षेत्र जैसा कि हमने देखा, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सामान्य रुप से अन्य विषयों में भी किया जाता है और तुलनात्मक राजनीति की विशिष्ट विषय-वस्तु, भाषा और परिप्रेक्ष्य वो तत्व हैं जो उसे उन अन्य विषयों से स्पष्टतया अलग करते हैं जो तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करते है। ऐसी स्थिति में, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का एक विशिष्ट क्षेत्र है या वह राजनीति विज्ञान के विस्तृत अध्ययन विषय में शामिल किया गया एक उप-अध्ययन विषय है। हमें यह याद रखना होगा कि विषय -वस्तु के तीन पहलू, भाषा, शब्दावली और परिप्रेक्ष्य राजनीति विज्ञान के व्यापक अध्ययन विषय के अन्तर्गत तुलनात्मक राजनीति की विशिष्टता को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त हैं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि तुलनात्मक राजनीति, राजनीति शास्त्र के विषय -वस्तु और चिंताओं में भागीदार है, जैसे, लोकतंत्र, संविधान, राजनीतिक दल, सामाजिक आन्दोलन इत्यादि। इस प्रकार, राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय के अन्तर्गत, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की विशिष्टता निर्दिष्ट होती है उसके द्वारा सचेत रुप से तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर देने में जिनमें राजनीति वैज्ञानिकों की सामान्य दिलचस्पी हो सकती है।

1.2.1 तुलनाएँ : संबंधों की पहचान

तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के चरित्र और विषय क्षेत्र को परिभाषित करने में तुलनात्मक पद्धति पर कुछ विद्वानों द्वारा यह बल दिया जाना, इस दृष्टि से कायम रखा गया है ताकि 'बाहरी देशों' या 'विदेशों' के अध्ययन के रुप में तुलनात्मक राजनीति से संबंधित लगातार गलतफहमियों को दूर किया जा सके। इस प्रकार की व्याख्या के अन्दर, यदि आप अपने से अलग किसी अन्य देश का अध्ययन कर रहे हों (उदाहरण के लिए, एक अमेरिकन ब्राज़ील की राजनीति का अध्ययन कर रहा हो अथवा एक भारतीय श्रीलंका की राजनीति का अध्ययन कर रहा हो) तो आपको एक तुलनावादी कहा जाएगा। आमतौर पर, इस गलतफहमी का अर्थ केवल व्यक्तिगत राष्ट्रों के बारे में सूचना एकत्रित करना होता है जिसमें तुलना थोड़ी ही मात्रा में या अधिक से अधिक अंतर्निहित होती है। अधिकांश तुलनावादी ये तर्क देंगे कि तुलनात्मक राजनीति की विशिष्टता उसके द्वारा दो या अधिक राष्ट्रों के अध्ययन के लिए तुलनाओं के एक सचेत और व्यवस्थित प्रयोग में है, जिसका उद्देश्य विश्लेषण की जा रही निश्चित परिघटनाओं के संबंध में उनके बीच भिन्नताओं या समानताओं की पहचान करना और अंततः उनकी व्याख्या करना है। एक लम्बे समय तक तुलनात्मक राजनीति मात्र समानताओं और भिन्नताओं को खोजती नज़र आई, और इसे उसने राजनीतिक परिघटनाओं का वर्गीकरण करने, द्विभाजित करने और ध्रुवित करने की ओर संचालित किया। परन्तु तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण केवल समानताओं और भिन्नताओं की पहचान करना नहीं है। अनेक विद्वानों का मानना है कि तुलनाओं के प्रयोग का उद्देश्य समानताओं और भिन्नताओं अथवा तुलना और विषमता उपागम के पार जाते हुए, अन्त में संबंधों के एक विस्तृत ढाँचे में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना है। ऐसा माना जाता है कि यह हमारी समझ की और गहन

करने में मदद करेगा और राजनीतिक परिघटनाओं का उत्तर देने और व्याख्या करने के स्तरों का विस्तार करेगा (मोहन्ती, 1975)।

1.2.2 तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार

रॉनल्ड चिलकॉट का दावा है कि संकल्पनात्मक उलझन के कारण, इस धारणा का अक्सर, सामना करना पड़ता है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकारों के अध्ययन से है। तुलनात्मक सरकार से भिन्न, जिसका क्षेत्र सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित है, तुलनात्मक राजनीति का संबध सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अध्ययन से है, सरकारी और गैर-सरकारी भी। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की एक 'सर्व-सम्मिलित' प्रकृति है और तुलनात्मक राजनीति के विशेषज्ञ, वह सब कुछ जो राजनीतिक है, उसके अध्ययन के रुप में इसे देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति की इससे लघु संकल्पना, इस क्षेत्र के अन्तर्गत अध्ययन से संबंधित चयन और अपवर्जन के मानदंडों को धुंधला कर देगी। (चिलकॉट, 1994 :4)

ये फिर भी कहा जा सकता है कि एक लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीति ने अपने आपको सरकारों और शासन प्रणालियों के प्रकार से संबंधित रखा और पश्चिमी देशों के अध्ययन तक सीमित रखा। विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने, विशेष रुप से द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरुप, 'नए राष्ट्रों' के अध्ययन में रूचि उत्पन्न की। तुलना के संम्पूर्ण विस्तार के अन्दर जिन इकाइयों/केस को लाया जा सकता था, उनकी संख्या और विविधता में वृद्धि के साथ-साथ सभी इकाइयों में राजनीतिक परिघटनाओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या करने वाले भावात्मक सर्वदेशीय प्रतिमानों को सूत्रबद्ध करने का आग्रह भी जुडा। लगभग इसी समय, अध्ययन के मामलों में वृद्धि और विविधता के साथ, राजनीति के क्षेत्र में भी एक विस्तार हुआ, जिसने एक सम्पूर्ण प्रणाली के रुप में राजनीति के परीक्षण का प्रबन्ध किया जिसमें न केवल राज्य और उसकी संस्थाएँ, बल्कि व्यक्ति, सामाजिक समूहीकरण, राजनीतिक दल, हित समूह, सामाजिक आन्दोलन इत्यादि भी शामिल किए गए। राजनीतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या के कुछ पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया, उदाहरण के लिए, राजनीतिक सामाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति के प्रतिरुप, हित अभिव्यक्ति की क्रियाविधियाँ और हित सामूहीकरण, राजनीतिक भर्ती की शैलियाँ, राजनीतिक प्रभावोत्पादकता और राजनीतिक उदासीनता की सीमा, सत्तारूढ़ अभिजातवर्ग इत्यादि। इप व्यवस्थित अध्ययनों का निर्माण अवसर राष्ट्र-निर्माण की चिन्ता के इर्द-गिर्द किया जाता था, अर्थात् एक जनता के लिए राजनीतिक-सांस्कृतिक पहचान की उपलब्धि करना, राज्य -निर्माण, अर्थात् राजनीति के लिए संस्थात्मक ढाँचे और प्रक्रियाओं की उपलब्धि करना और आधुनिकीकरण अर्थात् विकास के पाश्चात्य मार्ग की दिशा में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को प्रवर्तित करना। विश्व राजनीति में विचारधाराओं के भिन्न ध्रुवों नव-स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रों द्वारा पश्चिमी साम्राज्यवाद की अस्वीकृति, इन राष्ट्रों की अपनी विशिष्ट पहचान को कायम रखने की चिन्ता (जो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के उदय में सुस्पष्ट रुप से प्रतिबिंबित है) और विकास के समाजवादी मार्ग के प्रति अधिकांश राष्ट्रों में सहानुभूति ने धीरे-धीरे वैश्विक/व्यापक स्तरीय तुलनाओं के उद्देश्यों के लिए अधिकांश आधुनिकीकरण प्रतिमानों को अप्रासंगिक बना दिया। जहाँ एक ओर

पचास (1950) और आठ (1960) का दशक वो काल था जहाँ बड़े पैमाने के प्रतिमानों के निर्माण द्वारा राजनीतिक यथार्थ की व्याख्या करने का प्रयास किया गया, वहीं, सत्तर (1970) के दशक ने तृत्तीय विश्ववाद के दावे और इन प्रतिमानों के पीछे हटने को देखा। फिर अस्सी (1980) के दशक में हमने संकीर्ण और छोटी इकाइयों में तुलना के स्तर में संकुचन को देखा। परन्तु, वैश्वीकरण के साथ, व्यापक स्तरीय तुलनाओं की अनिवार्यताओं में वृद्धि हुई और गैर-राज्कीय, गैर-सरकारी पात्रों के फैलाव और आर्थिक संयोजन और सूचना टेक्नॉलजी क्राँति के साथ राष्ट्रों के बीच अंतःसंबंधों में वृद्धि के साथ तुलनाओं का क्षेत्र विविधतापूर्ण हो गया है।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) इकाई के अन्त में अपने उत्तर के लिए संकेतों को देखें।

1. तुलनात्मक सरकार किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति से भिन्न है?

.....

.....

.....

.....

.....

1.3 तुलनात्मक राजनीति :एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन

ऐतिहासिक दृष्टि से उसकी विषय -वस्तु में परिवर्तनों के साथ तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र में बदलाव आया है। तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु का निर्धारण भौगोलिक स्थान (अर्थात् राष्ट्र, क्षेत्र) जिसने क्षेत्र को संस्थापित किया है और साथ-साथ सामाजिक यथार्थ और परिवर्तन से संबंधित प्रधान विचारों, जिन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के उपागमों (पूँजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और देशज) को आकार दिया है,इन दोनों के द्वारा किया गया है। उसी प्रकार, भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में, अध्ययन का दबाव या प्राथमिक चिन्ता बदलती रही है।

1.3.1 राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की उत्पत्ति

तुलनात्मक राजनीति की एक लम्बी बौद्धिक वंशावली है, अरस्तू तक पीछे जाते हुए और निक्कोलो मेक्यावली, जॉन लॉक, मैक्स वेबर इत्यादि जैसे चिंतकों द्वारा जारी रखी गई। अपने सबसे प्रारंभिक अवतार में, राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन हमारे पास यूनानी दार्शनिक अरस्तू के द्वारा किए गए अध्ययनों के रुप में आता है। अरस्तू ने 150 राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया और उनका शासन प्रणालियों के प्रारुप में वर्गीकरण किया। उसका वर्गीकरण वर्णनात्मक और मानकीय, दोनों श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया, अर्थात् उसने न केवल शासन प्रणालियों और राजनीतिक प्रणालियों का वर्णन और वर्गीकरण उनके प्रकार के अनुसार किया, उदाहरण के लिए, लोकतंत्र, कुलीनतंत्र, राजतंत्र इत्यादि बल्कि

सुशासन के कुछ निश्चित मानकों के आधार पर उन्हें श्रेणीबद्ध भी किया। इस तुलना के आधर पर, उसने शासन प्रणालियों को अच्छे और बुरे–आदर्श और विकृत में विभाजित किया। इन अरस्तूवादी श्रेणियों को पॉलिबियस (201–120 ई. पूर्व) और सिसेरो (106–43 ई.पूर्व) जैसे प्राचीन रोमन चिंतकों इनपर औपचारिक और कानूनी आधारों पर विचार करते हुए इन्हें स्वीकृति दी और आगे बढ़ाया। शासन प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन में दिलचस्पी 15 वीं सदी में मेक्यावली (1469–1527) के साथ पुनः प्रकट हुई जिसने विभिन्न प्रकार की जागीरों (वंशानुगत, नई, मिश्रित और गिरजे-संबंधी) और गणराज्यों की तुलना की ताकि उन्हें शासित करने के सबसे सफल तरीकों तक पहुँचा जा सके।

1.3.2 उन्नीसवीं सदी का अन्त और बीसवीं सदी का प्रारंभ

उन्नीसवीं सदी के अन्त और बीसवीं सदी के प्रारंभ के तुलनात्मक अध्ययनों में 'उत्तम व्यवस्था' या 'आदर्श राज्य' से संबंधित दार्शनिक और काल्पनिक प्रश्नों के साथ ध्यानमग्नता और इस प्रक्रिया में भावात्मक और मानकीय शब्दावली का प्रयोग कायम रहा। ये वो समय था जब उदारवाद सबसे प्रबल विचारधारा थी और यूरोपीय राष्ट्र विश्व राजनीति पर अपरिहार्य प्रभुत्व का आनन्द ले रहे थे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की शेष दुनिया या तो यूरोपीय उपनिवेश थी या भूतपूर्व उपनिवेशों के रुप में उनके प्रभाव क्षेत्र में थी। इस काल के दौरान अपनाए गए तुलनात्मक अध्ययनों, जैसे जेम्स ब्राइस का मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ (1921), हर्मन फाइनर का थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स (1932) और कार्ल जे. फ्राइडरिक का कॉंस्टिटयूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी (1937), रॉबेर्नो निकेल्स का पोलिटिकल पार्टीज़ (1915) की दिलचस्पी प्रधान रुप से संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन, शक्ति का वितरण, और सरकार की विभिन्न परतों के बीच संबंध में थी। ये अध्ययन 'यूरो-केंद्रित' थे, अर्थात् ब्रिटेन, फ्राँस और जर्मनी जैसे यूरोपीय राष्ट्रों में संस्थाओं, सरकारों और शासन प्रणाली के प्रकारों के अध्ययन तक सीमित थे। अतः ये कहा जा सकता है कि ये अध्ययन वास्तव में इस दृष्टि से विशुद्ध रुप से तुलनात्मक नहीं थे कि इन्होंने बड़ी संख्या में राष्ट्रों को अपने विश्लेषण से बहिष्कृत किया। कुछ ही राष्ट्रों तक सीमित अध्ययन से प्राप्त किया गया सामान्यीकरण बाकी के विश्व के लिए मान्यता का वैध दावा नहीं कर सकता था। यहाँ इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि बाकी के विश्व का बहिष्कार, विश्व राजनीति में यूरोप का प्रभुत्व का सूचक था। सभी समकालीन इतिहास के केन्द्र में यूरोप रहा, बाकी के विश्व का अभिलोपन (मिटाते) करते हुए (उपनिवेशित या उपनिवेशवाद से मुक्त) (क) 'बिना इतिहास के जन' के रुप में या (ख) जिनके इतिहास पश्चिम के उन्नत देशों से जुड़े थे और उन प्रक्षेप- पंथों का अनुसरण करने के लिए नियत थे जिन्हें पश्चिम के उन्नत देशों ने पहले से अपना रखा था। इस प्रकार उपरोक्त कृतियाँ पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के मानक मूल्यों में अपने दृढ आधार को अभिव्यक्त करती हैं जिसने अपने साथ नृजातीय और सभ्यतागत श्रेष्ठता का सामान ढोया, और उपनिवेशों/भूतपूर्व उपनिवेशों के लिए एक आदेशात्मक चरित्र धारण किया।

1.3.3 द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पश्चात्

उन्नीससौतीस के दशक में विश्व की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। सन् 1917 में रूस में बोल्शेविक क्राँति ने विश्व में समाजवाद को

उत्पीड़ितों की एक विचारधारा के रुप में और पश्चिमी उदारवाद और पूँजीवाद के एक आलोचनात्मक विकल्प के रुप में उत्पन्न किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त के साथ, तक महत्वपूर्ण घटनाएँ घट चुकी थीं, जिनमें यूरोपीय (ब्रिटीश) वर्चस्व का पतन, विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका का 'नए अधिपति' के रुप में उत्थान और मोर्चाबंदी, और विश्व का विचारधारा की दृष्टि से दो गुटों में बंटवारा अर्थात् (पश्चिमी) पूंजीवाद और (पूर्वी) समाजवाद शामिल थे। जब तक द्वितीय विश्व युद्ध का अन्त हुआ, 'बाकी के विश्व' के अधिकांश हिस्से ने अपने को यूरोपीय साम्राज्यवाद से मुक्त कर लिया था। विउपनिवेशीकरण की एक अवधि के पश्चात् विकास, आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण, राज्य -निर्माण इत्यादि विचारों ने 'राष्ट्रीय नारों' के रुप में 'नए राष्ट्रों' के राजनीतिक अभिजनों के बीच वैधता के एक स्तर और यहाँ तक कि लोकप्रियता को भी प्रदर्शित किया। परन्तु वैचारिक दृष्टि से ये 'नए राष्ट्र' विकास के पश्चिमी पूंजीवाद मार्ग को अपनाने के लिए अब मजबूर नहीं थे। जहाँ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए सत्ताधारी अभिजनों के बीच समाजवाद के अपने हिस्से के समर्थक थे, वहीं नव-स्वतंत्रता प्रापत देशों ने दोनों शक्ति गुटों से निरपेक्ष रहते हुए, अपने को उनसे दूर रखने का चेतनापूर्ण निर्णय लिया। इनमें से अनेक देशों ने, समाजवाद से मिलते-जुलते, विकास के अपने विशिष्ट मार्ग को विकसित किया जैसा कि तांज़ानिया में उज्जामा के मामले में और भारत में मिश्रित-अर्थव्यवस्था का मॉडल, जो पूँजीवाद और समाजवाद का मिश्रण था।

यह याद रखने योग्य है कि 1940 के दशक तक सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रधान रुप से संस्थाओं, उन्हें नियमित करने वाले कानूनी-संवैधानिक सिद्धांतों, और पश्चिमी (यूरोपीय) उदारवादी लोकतंत्रों में उनकी कार्य शैली का अध्ययन था। उपराक्त गतिविधियों के संदर्भ में, 1950 के दशक के मध्य में, संस्थात्मक उपागम की एक सशक्त समालोचना की उत्पत्ति हुई। इस समालोचना की जड़ें व्यवहारवाद में थीं जिसका उदय राजनीति के विषय में एक नए आन्दोलन के रुप में हुआ, जिसका उद्देश्य विश्व को वैज्ञानिक कठोरता उपलब्ध कराना और राजनीति के एक विज्ञान को विकसित करना था। 'व्यवहारवादी आन्दोलन' के नाम से प्रसिद्ध, इसकी दिलचस्पी एक अन्वेषण को विकसित करना था जो परिमाणात्मक हो और जो मूल्यों से पृथक अनुभाविक तथ्यों के परीक्षण के लिए सर्वेक्षण तकनीकों पर आधारित हो ताकि मूल्य -तटस्थ, गैर-आदेशात्मक, वस्तुनिष्ठ टिप्पणियाँ और व्याख्याएँ उपलब्ध की जा सकें। व्यवहारवादियों ने 'लोग राजनीतिक दृष्टि से व्यवहार क्यों करते हैं, जैसा कि वे करते हैं और क्यों उसके परिणामस्वरुप राजनीतिक प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ वैसे कार्य करती हैं, जैसा ि कवे करती हैं जैसे प्रश्नों के उत्तर की खोज करते हुए सामाजिक यथार्थ के अध्ययन का प्रयास किया। लोगों के व्यवहारों में भिन्नताओं और राजनीति प्रक्रियाओं और राजनीतिक प्रणालियों के लिए उनके निहितार्थों के संबंध में इन 'क्यों' प्रश्नों ने संस्थाओं के कानूनी-औपचारिक पहलुओं से तुलनात्मक अध्ययन के केन्द्रबिन्दु को बदल दिया। इस प्रकार, 1955 में रॉय मेकरिडिस ने गैर-औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं से अधिक, औपचारिक संस्थाओं का विशेषाधिकरण करने, विश्लेषणात्मक होने के स्थान पर केस-स्टडी उन्मुख होने के लिए मौजूदा तुलनात्मक अध्ययनों की आलोचना की (मेकरिडिस, 1955) हेरी एक्स्टीन इस ओर ध्यान दिलाता है कि इस अवधि के दौरान

तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र में परिवर्तन राजनीति की धारणा की पुनर्संकल्पना और व्यापक पैमाने पर तुलनाओं के विकास की आवश्यकता का आग्रह करते हुए बदलती हुई विश्व राजनीति के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाते हैं (एक्स्टीन, 1963) तत्कालीन पारम्परिक और पश्चिमी विश्व पर लगभग अनन्य बल तथा इतनी सीमित तुलनाओं को ध्यान में रखते हुए जिस संकल्पनात्मक भाषा को विकसित किया गया था, इन सबको अस्वीकार करते हुए गैब्रील आमंड और अमेरिकन सोशल साईन्स रिसर्च काऊंसिल की कमिटी ऑन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स (1954 में स्थापित) में उनके सहकर्मियों ने एक सिद्धांत और एक पद्धति को विकसित करना चाहा जो सभी प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों को सम्मिलित करते हुए उनकी तुलना कर सके–आदिम या उन्नत, लोकतांत्रिक या गैर-लोकतांत्रिक, पश्चिमी या गैर-पश्चिमी।

एक भौगोलिक या प्रादेशिक दृष्टि से मामलों के विस्तार के साथ स्वयं राजनीति के बोध का भी विस्तार हुआ और विशेष रुप से उसकी अस्वीकृति द्वारा जिसे उस समय औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में पारंपरिक और संकीर्ण रुप से परिभाषित बलाघात के रुप में देखा गया था। मात्र 'विधिवादिता' से भिन्न 'यथार्थवाद' या 'व्यवहार में' राजनीति पर बल द्वारा राजनीति की धारणा का विस्तार किया गया। इसने, इसके विषय क्षेत्र में औपचारिक दृष्टि से कम मात्रा में संरचनाबद्ध अभिकरणों, व्यवहारों और प्रक्रियाओं की कार्यप्रणाली को शामिल किया, उदाहरण के लिए, राजनीतिक दल, हित समूह, चुनाव, मतदान व्यवहार, मनोवृति इत्यादि। औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन से ध्यान हटने के साथ, समानांतर रुप से स्वयं राज्य की धारणा की केन्द्रीयता का पतन हुआ। हमने इससे पूर्व उल्लेख किया था कि विश्व मंच पर बडी संख्या में राष्ट्रों के उदय ने ढ़ाँचों के विकास को अनिवार्य बना दिया जो व्यापक पैमाने पर तुलनाओं को सरल बनाएँगे। इसके फलस्वरुप राजनीतिक प्रणाली जैसी समावेशी और भावात्मक धारणाओं का उदय हुआ। 'प्रणाली' की इस धारणा ने राज्य की धारणा का स्थान ले लिया और विद्वानों को 'विधि-तर', 'सामाजिक' और 'सांस्कृतिक' संस्थाओं पर विचार करने में सक्षम बनाया, जो गैर-पश्चिमी राजनीति को समझने के लिए अत्यन्त आवश्यक थे। इस धारणा का अतिरिक्त लाभ ये था कि इसके विषय -क्षेत्र में 'राज्य से पूर्व'/गैर-राज्कीय समाजों को और साथ ही भूमिकाओं और पदों को शामिल किया गया जिन्हें प्रत्यक्ष रुप से राज्य से संबंधित नहीं देखा गया। इसके अतिरिक्त, संस्थाओं के वास्तविक व्यवहारों और कार्यों पर बल दिए जाने में परिवर्तन के साथ, अनुसंधान की समस्याओं को इन संस्थाओं की कानूनी शक्तियों की दृष्टि से परिभाषित नहीं किया गया,बल्कि इस दृष्टि से कि वे वास्तव में क्या करते थे, वे एक-दूसरे से कैसे संबंधित थे और लोकनीति के निर्माण और कार्यान्वयन में उनकी क्या भूमिकाएँ थीं। इसके परिणामस्वरुप, संरचनात्मक-कार्यात्मक उपागम का उदय हुआ जिसमें कुछ निश्चित कार्यों को सभी समाजों के लिए अनिवार्य बताया गया और इन कार्यों के कार्यान्वयन और अनुपालन की तब तुलना विभिन्न प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक ढ़ाँचों के आर-पार की जानी थी। यद्यपि प्रणालियों के सार्वभौमिक ढ़ाँचों और संरचनाओं-कार्यों ने पश्चिमी विद्वानों को राजनीतिक प्रणालियों, संरचनाओं और व्यवहारों की एक विस्तृत श्रेणी का एक एकल प्रतिमान के अन्तर्गत अध्ययन करने में सक्षम बनाया, 'नए राष्ट्रों' के आगमन ने पश्चिमी तुलनावादियों को उस

वस्तु का अध्ययन करने का अवसर दिया जिसे उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के रुप में देखा। वियार्ड ध्यान दिलाता है कि साठ के दशक (1960) की इस अवधि में ही तुलनात्मक राजनीति के अधिकांश समकालीन विद्वान विकास की पराकाष्ठा तक पहुँचे। इनमें से अधिकांश विद्वानों के लिए (व्यंगात्मक रुप से) 'नए राष्ट्र', सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए 'जीवित प्रयोगशालाएँ' बन गए। वियार्ड उन 'उत्तेजक दिनों' का वर्णन करता है जिन्होंने राजनीतिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए अनोखे अवसर प्रदान किए और नई पद्धतियों और उनके अध्ययन के उपागमों के विकास को देखा। इस अवधि के दौरान ही तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में कुछ सर्वाधिक अभिनव और उत्तेजक सैद्धांतिक और संकल्पनात्मक उपागमों को प्रस्तुत किया गया : राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन, राजनीतिक सामाजीकरण, विकासवाद, पराश्रितता और परस्पर निर्भरता, कॉरपोरेटवाद (सामूहिक नियंत्रणवाद), नौकरशाही-अधिनायकवाद और लोकतंत्र की दिशा में बाद के परिवर्तन इत्यादि (वियार्ड, 1998) इस अवधि में सार्वभौमवादी मॉडल (प्रतिमानों) की बाढ़ लग गई जैसे डेविड ईस्टन का 'पोलिटिकल सिस्टम', कार्ल ड्यूश का 'सोशल मोबिलाइज़ेशन' और एडवर्ड शिल का 'सेन्टर एंड पेरिफेरी'। ऐंप्टर, रोक्कन, आइज़ेनस्टाड्ट और वॉर्ड के आधुनिकीकरण के सिद्धांत और आमंड, कोल्मेन, पइ और बर्बा के राजनीतिक विकास के सिद्धांत ने भी सार्वभौमिक प्रासंगिकता का दावा किया। इन सिद्धांतों का सांस्कृतिक और विचारधारा की सीमाओं के आर-पार लागू होने और इनके द्वारा सर्वत्र राजनीतिक प्रक्रिया की व्याख्या करने का दावा किया गया। इस अवस्था में, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के विकास ने सैनिक संधियों और विदेशी सहायता के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से मेल खाया। इस अवधि के दौरान का अधिकांश अध्ययन न केवल अनुसंधान संस्थान द्वारा वित्तपोषित किया गया बल्कि उसे अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुकूल भी बनाया गया। इनमें से सबसे प्रतीकात्मक थे लैटिन अमेरिका में 'प्रॉजेक्ट केमलॉट' और भारत में 'हिमालयन प्रॉजेक्ट'। इस अवधि की घोषणा धाना पर ऐप्टर के अध्ययन जैसी कृतियों के प्रकाशन द्वारा हुई। 1960 में प्रकाशित आमंड और कोल्मेन की 'पॉलिटिक्स ऑफ डेवेलपिंग एरियास' ने नए तुलनात्मक राजनीति आन्दोलन' के चरित्र को परिभाषित किया। 1969 में अमेरिका में 'कंपेरेटिव पॉलिटिक्स' शीर्षक से प्रकाशित एक नई पत्रिका ने इस प्रवृत्ति की पराकाष्ठा को प्रतिबिंबित किया (मोहन्ती, 1975)। 'विकासवाद' शायद इस समय का प्रधान संकल्पनात्मक प्रतिमान था। काफी हद तक, विकासवाद में दिलचस्पी 'विकासशील राष्ट्रों' में अमेरिकी विदेश नीति के हितों से उत्पन्न हुई ताकि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आकर्षणों का विरोध हो सके और उन्हें विकास के एक गैर-साम्यवादी पथ की ओर अभिमुख किया जा सके (वियार्ड, 1998)।

उत्तर-व्यवहारवाद

व्यवहारवादी क्राँति के समर्थक जो राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक कठोरता लाना चाहते थे, इस बात से निराश हुए कि ये विषय उस समय के सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में न तो पूर्वानुमान कर पाया और न ही अध्ययन : उसके नए पर्यावरणीय और नारीवादी आन्दोलन, उसका युद्ध -विरोधी परिप्रेक्ष्य, नागरिक अधिकारों से संबंधित उसकी चिंताएँ इत्यादि। उनके द्वारा दो बलों के बीच सामंजस्य स्थापित

करने के प्रयास : राजनीति विज्ञान को और कठोर और अधिक प्रासंगिक बनाने के परिणामस्वरुप उत्तर-व्यवहारवादी आन्दोलन हुआ। 1969 में डेविड ईस्टन का अमेरिकन पोलिटिकल स्टडीज़ एसोसियेशन्स का अध्यक्षीय अभिभाषण इस आन्दोलन की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति करता है। ईस्टन ने 'प्रासंगिकता के सिद्धांत' की रुपरेखा निम्नलिखित सात मूल सूत्रों के साथ प्रस्तुत की जो उत्तर-व्यवहारवादी आन्दोलन का प्रमाण-चिन्ह बन गए।

- तत्व का तकनीक पर प्रभुत्व होना चाहिए। क्या अध्ययन किया जाता है, ये इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसका कैसे अध्ययन किय जाता है।
- राजनीति जैसी है, उनका अनुभाविक अध्ययन मात्र करने का दावा एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण का समर्थन करना है क्योंकि वह जो है, उसपर ध्यान केंद्रित करता है, न कि उस पर जो संभव है।
- पद्धति में अत्यधिक कृत्रिमता अधिकांश राजनीति के क्रर यर्थाथ को धुंधला कर देती है और राजनीति विज्ञान को अत्यावश्यक मानवीय जरुरतों को संबोधित करने से रोकती है।
- विज्ञान निरपेक्ष नहीं हो सकता : आप किस विषय के अध्ययन का चयन करते हैं, यह मतावलोकन द्वारा संचालित होता है और उस कार्य का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए वह मूल्यों द्वारा परिचालित होना चाहिए।
- बुद्धि जीवियों की भूमिका 'सभ्यता के मानवोचित मूल्यों' को प्रोत्साहित करना है।
- जानने का अर्थ है, करने के दायित्व को निभाना ; अपने ज्ञान को कार्यान्वित करना वैज्ञानिकों का एक विशेष कर्तव्य है।
- संलग्न होने की यह प्रतिबद्धता संस्थागत होनी चाहिए और विद्वानों और विश्वविद्यालयों के संघों के माध्यम से अभिव्यक्त होनी चाहिए। वे अलग खडे नहीं रह सकते : व्यवसायों का राजनीतिकरण अपरिहार्य है और वांछनीय भी।

1.3.4 1970 के दशक और विकासवाद की चुनौतियाँ

1970 के आसपास भावात्मक प्रतिमानों का पक्ष लेने के कारण विकासवाद की आलोचना हुई उसने विशिष्ट राजनीतिक/सामाजिक/सांस्कृतिक प्रणालियों के बीच भिन्नताओं को दबाया ताकि उनका अध्ययन एक एकल सार्वभौमवादी संरचना के अन्तर्गत किया जा सके। इन आलोचनाओं ने इन प्रतिमानों की 'नृजातीयता' पर बल दिया और अल्पविकास के एक सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिए तृतीय विश्व पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने विकासशील राष्ट्रों के पिछडेपन के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 1970 के दशक के प्रारंभिक काल में विकासवाद के लिए जो दो मुख्य चुनौतियाँ उत्पन्न हुई और जिन्होंने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, वे भी (क) पराश्रितता और (ख) कॉर्पोरेटवाद। पराश्रितता के सिद्धांत ने विकास में घरेलू वर्ग कारकों और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार और शक्ति कारकों की अनदेखी के लिए विकासवाद के प्रधान मॉडल (प्रतिमान) की आलोचना की। इसने अमेरिकी विदेश नीति और बहुराष्ट्रीय निगमों की विशेष रुप से आलोचना की और जिसे विकासवाद में सत्य माना गया था, उसके विपरीत, ये सुझाव दिया कि पहले से ही औद्योगीकृत राष्ट्रों का और विकासशील राष्ट्रों का विकास एक साथ नहीं हो सकता। इसके स्थान पर, पराश्रितता के सिद्धांत ने तर्क दिया कि पश्चिम का

विकास, गैर-पश्चिम के कंधों पर और उनके विकास की कीमत पर हुआ था। इस विचार को कि पूँजीवाद का प्रसार विश्व के अनेक हिस्सों में, विकास को नहीं, अल्पविकास को प्रोत्साहित करता है, आंद्रे गुंडर फ्रैंक के 'केपिटलिज़्म एंड अंडर-डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका' (1967), वॉल्टर रॉडनी के 'हाऊ यूरोप अंडरडेवलप्ड़ आफ्रीका' (1972) और मॉल्कम कैल्डवैल के 'द वेल्थ ऑफ सम नेशन्स' (1979) में सम्मिलित किया गया। परन्तु पराश्रितता के सिद्धांत के मार्क्सवादी आलोचकों ने इस ओर ध्यान दिलाया कि अधिशेष निष्कर्षण के माध्यम से शोषण की प्रकृति को केवल राष्ट्रीय स्तर पर न देखकर, केन्द्र के महानगरीय बुर्जुआ आश्रैर परिधि के देशज बुर्जुआ द्वारा विश्व-व्यापी पूँजीवादी प्रणाली में क्रियाशीलता के दौरान, उनके बीच गठबंधनों के एक अधिक जटिल प्रतिमान के हिस्से के रुप में देखा जाना चाहिए। कॉर्पोरेटवादी उपागम ने विकासवाद की उसकी यूरो-अमेरिकन नृजातिकेंद्रण के लिए आलोचना की और ये संकेत दिया कि राज्य और राज्य -समाज संबंधों को संगठित करने के वैकल्पिक जैविक, कॉर्पोरेटवादी, अक्सर सत्तावादी तरीके हैं। (चिलकॉट, 1994 : 16)

1.3.5 1980 के दशक : राज्य की वापसी

1970 के दशक के अन्त और 1980 के दशक के प्रारंभिक काल के दौरान, विकासवाद के विरुद्ध तीखी प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित करते हुए, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अनेक सिद्धांतों और विषय वस्तुओं का उदय हुआ। इनमें नौकरशाही-सत्तावाद, परिवर्तन की देशज अवधारणाएँ, लोकतंत्र की दिशा में परिवर्तन, संरचनात्मक समायोजन की राजनीति, नव-उदारवाद और निजीकरण शामिल थे। जहाँ कुछ विद्वानों ने इन गतिविधियों को उस क्षेत्र की एकता को दुर्बल बनाने और तोडने के रुप में देखा, जिस पर विकासवाद का प्रभुत्व था, वहीं दूसरों ने इन्हें स्वस्थ विविधता को जोडने, वैकल्पिक उपागमों को उपलब्ध करने और नए विषय क्षेत्रों का प्रतिपादन करने के रुप में देखा। आमंड, जिसने 1950 के दशक के अन्त में ये तर्क दिया था कि राज्य की धारणा का स्थान राजनीतिक प्रणाली को मिलना चाहिए जो वैज्ञानिक अन्वेषण के अनुकूलनीय थी, और ईस्टन, जिसने एक राजनीतिक प्रणाली के मानदंडों और अवधारणाओं के निर्माण का दायित्व लिया था, 1980 के दशक के मध्य तक भी राजनीकि अध्ययन के केन्द्र के रुप में राजनीतिक प्रणाली के महत्व पर उसने तर्क प्रस्तुत किया। फिर भी साठ और सत्तर के दशकों में लैटिन अमेरिका में नौकरशाही सत्तावाद की कृतियों में राज्य को अपने हिस्से की मान्यता मिली विशेष रुप से आर्जेंटीना में ग्वियेर्मो ओ 'डॉनल की कृतियों में, उदाहरण के लिए 'इकोनॉमिक मॉडर्नाइज़ेशन एंड ब्यूरोक्रैटिक अथॉरिटेरियनिज़्म' (1973)। रैल्फ मिलिबैंड की 'द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी' (1969) ने भी दिलचस्पी को कायम रखा। निकोस पूलांट्ज़ास की 'स्टेट, पावर, सोशलिज़्म' (1978) और राजनीतिक समाजवादियों पीटर एवन्स, थेडा स्कोक्पॉल एवं अन्य की 'ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन' (1985) के साथ राज्य पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया।

1.3.6 बीसवीं सदी का अंत : वैष्वीकरण और उभरती हुई प्रवृत्तियाँ / संभावनाएँ

क) प्रणालियों का अवश्रणियन : 1960 से 1980 की अवधि में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के अधिकांश विकास को केस के रुप में देखा जा सकता है, जिसमें और चरों को मॉडल (प्रतिमानों) से जोडा गया जैसे नीति, विचारधारा, शासनकार्य का अनुभव इत्यादि। फिर भी, 1980 के दशक में, सामान्य सिद्धांत से हटकर, संदर्भ की प्रासंगिकता पर बल देने की दिशा में परिवर्तन हुआ। आंशिक रुप से, ये प्रवृत्ति सामाजिक विज्ञानों में ऐतिहासिक अन्वेषण के नवीकृत प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है, और विशेष रुप से एक 'ऐतिहासिक समाजशास्त्र' की उत्पत्ति को जो परिघटनाओं को उस अत्यन्त विस्तृत या 'समग्र' संदर्भ में समझने का प्रयास करता है जिसमे वे घटित होती हैं (थेडा स्कोक्पॉल और एम. सॉमर्स, 1980)। मॉडल्स से दूर हटने हटते हुए निश्चित राष्ट्रों और केस की और गहन समझ की ओर परिवर्तन हुआ है जहाँ अधिक गुणवतात्मक और संद्र्भित डेटा (आँकडों) का मूल्यांकन किया जा सकता है और जहाँ विशिष्ट संस्थात्मक परिस्थितियों या निश्चित राजनीतिक संस्कृतियों का ध्यान रखा जा सकता है। अतः हम सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक विशिष्ट अध्ययनों (उदाहरण के लिए, अंग्रेजी बोलने वाले राष्ट्र, इस्लामी राष्ट्र), और राष्ट्रीय दृष्टि से विशिष्ट राष्ट्रों (उदाहरण के लिए इंग्लैंड, भारत), और यहाँ तक कि संस्थात्मक दृष्टि से विशिष्ट राष्ट्रों (उदाहरण के लिए एक विशिष्ट शासन प्रणाली के अधीन भारत) पर नया जोर देखते हैं। जहाँ 'भव्य प्रणालियों' और मॉडल निर्माण पर बल घटा, वहीं विशिष्ट संदर्भों और संस्कृतियों पर बल देने का अर्थ ये रहा है कि तुलनाओं के पैमाने को नीचे लाया गया। 'छोटी प्रणालियों' या क्षेत्रों के स्तर पर तुलनाएँ कायम रहीं, उदाहरण के लिए, इस्लामी विश्व, लैटिन अमेरिका के राष्ट्र, उप-सहारा आफ्रीका, दक्षिणी एशियया इत्यादि।

ख) नागरिक समाज और लोकतांत्रीकरण उपागम : सोवियत संघ के विघटन ने 'इतिहास का अन्त' धारणा का प्रचलन किया। अपने लेख "द एंड ऑफ हिस्ट्री?" (1989), जिसे आगे चलकर 'द एंड ऑफ हिस्ट्री एण्ड द लास्ट मैन' (1992) शीर्षक से पुस्तक के रुप में विकसित किया गया, फ्राँसिस फुकुयामा ने तर्क दिया कि' मानव सरकार के अंतिम रुप' में उदारवादी लोकतंत्र की मान्यता और विजय के साथ, विचारों का इतिहास समाप्त हो चुका था। पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र की प्रधानता पर बल देने के लिए 'इतिहास का अंत' निबन्ध का प्रयोग, एक प्रकार से 1950 के दशक की 'विचारधारा का अंत' बहस की याद दिलाता है शीत युद्ध की पराकाष्ठा के दौरान और पश्चिम में साम्यवाद के पतन के संदर्भ में उत्पन्न हुई थी। पश्चिमी उदारवादी विद्वानों ने प्रस्तावित किया कि पश्चिम के औद्योगीकृत समाजों में हुई आर्थिक उन्नति ने उन कल्पित राजनीतिक समस्याओं का हल कर दिया था जो औद्योगीकरण के साथ चलते हैं, उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता के मुद्दे और राज्य शक्ति, श्रमिकों के अधिकार इत्यादि। विशिष्ट रुप से, अमेरिकी समाजशास्त्री, डैनियल बेल ने अपनी कृति 'द एंड ऑफ आइडियॉलजी? : ऑन द एग्ज़ॉशन ऑफ पोलिटिकल

आइडियास इन द 1950 ज़', (1960) में ध्यान दिलाया कि इस गतिविधि के कारण एक वैचारिक सर्वसम्मति थीं, या राजनीतिक व्यवहार के मुद्दों के संबंध में विचारधारात्मक मतभेदों की आवश्यकता के स्थगन की थी। नब्बे के दशक के पूर्वार्ध में 'एंड ऑफ हिस्ट्री' के विचार को अस्सी के दशक की एक अन्य परिघटना से जोडा गया, 'वैश्वीकरण'। वैश्वीकरण परिस्थितियों के एक समूह से संबंध रखता है, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्होंने विश्व को इस तरह जोड़ दिया है कि विश्व के एक हिस्से की घटनाएँ, एक अन्य हिस्से की घटनाओं को निश्चित रुप से प्रभावित कर सकती हैं या उनके द्वारा प्रभावित हो सकती हैं। ये उल्लेख किया जा सकता है कि वैश्विक विश्व में वह केन्द्रबिन्दु या केन्द्र जिसके चारों ओर घटनाएँ विश्व भर में घटित होती हैं, वह अभी भी पश्चिमी पूँजीवाद है। तथाकथित पूँजीवाद के विजय के संदर्भ में, नागरिक समाज और लोकतंत्रीकरण के अध्ययन के जिन उपागमों को लोकप्रियता प्राप्त हुई है, वे नागरिक समाज को महत्व देते हैं जिसे आधुनिक पूँजीवादी विश्व में प्रवेश के लिए व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के संबंध में परिभाषित किया गया है।

डपागम में, फिर भी एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पाई जाती है जो नागरिक समाज और लोकतंत्रीकरण के प्रश्नों को अपना प्राथमिक केन्द्रबिंदु बनाना चाहती है। यदि एक ओर बाज़ारी लोकतंत्र के विकास में जुटे पश्चिमी पूँजीवाद की समकालीन दिलचस्पी के अनुकूल अध्ययन पाए जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर ऐसे अनेक अध्ययन भी पाए जाते हैं जो स्वायत्तता की माँग, देशज संस्कृति के अधिकार से जुड़े जन आन्दोलनों, जनजातियों, दलितों, निम्न जातियों के आन्दोलनों, और नारी आन्दोलन और पर्यावरण आन्दोलन के पुनरुत्थान पर विचार करते हैं, जहाँ पूँजी के हित, जनता के हितों के विरोध में होते हैं और वैश्विक पूँजी के दौर में परिवर्तन और मुक्ति की भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः पहचान, पर्यावरण, नृजातीयता, लैंगिकता, जाति इत्यादि के मुद्दों से संबंधित चिन्ताओं ने तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण को एक नया आयाम दिया है।

ग) **सूचना संकलन और प्रसार** : सूचना एवं संचार टैक्नॉलजी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू और कारका रहा है। इसने डेटा (आँकडों) के उत्पादन, संकलन और विश्लेषण को और सरल बना दिया है और विश्वभर में उनके अधिक तेज और विस्तृत प्रसार को सुनिश्चित कर दिया है। इन परिवर्तनों ने न केवल डेटा की उपलब्धि में वृद्धि की है, बल्कि नए मुद्दों और प्रकरणों की उत्पत्ति को संभव बनाया है जो राष्ट्र-राज्य के दायरे के पार विस्तृत होते हैं। बदले में नए प्रकरण समकालीन वैश्वीकृत विश्व के राजनीतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण/प्रभावशाली पहलू बनते हैं। सामाजिक आन्दोलन संगठनों का वैश्विक तंत्र, सक्रियतावादियों का वैश्विक तंत्र इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोकतंत्रीकरण के विचारों का प्रसार ऐसे तंत्रीकरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। मेक्सिको के दक्षिणी प्राँत कियापास में ज़पास्तिस्ना विद्रोह ने अधिकारों, सामाजिक इंटरनेट और वैश्विक मीडिया का प्रयोग किया। मानव अधिकारों के

प्रोत्साहन और संरक्षण से जुडे मुद्दों के संबंध में चिन्ता, जो समकालीन विश्व में प्रासंगिक बन गई है।

बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) इकाई के अन्त में अपने उत्तर के लिए संकेतों को देखें।

1) क्या ये कहना संभव है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल सरकारों के अध्ययन की एक पद्धति से है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और विषय -क्षेत्र का विकास विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में बदलती हुई सामाजिक-राजनीतिक चिंताओं की प्रतिक्रिया के रुप में हुआ है। टिप्पणी करें।

.....

.....

.....

.....

.....

1.4 राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन : उपयोगिता

तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता का प्रश्न राजनीतिक यथार्थ के संबंध में हमारी समझ को बढ़ाने में इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता से है। इसका उद्देश्य ये जानकारी प्राप्त करना है कि इस यर्थाथ को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन हमारी किस प्रकार सहायता करता है। प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमें ये ध्यान में रखना होगा कि राजनीतिक व्यवहार सभी मनुष्यों के लिए सामान्य है और विश्व भर में इसकी अभिव्यक्ति अनेक विधियों से और अनेक सामाजिक और संस्थात्मक व्यवस्थाओं में होती है। ये कहा जा सकता है कि इन संबंधित और समानांतर रुप से भिन्न राजनीतिक व्यवहारों और प्रतिमानों की समझ स्वयं राजनीति के बारे में हमारी समझ का एक अभिन्न हिस्सा है। सामान्य तौर पर, एक ठोस और विस्तृत समझ तुलनाओं का रुप लेगी।

1.4.1 सैद्धांतिक सूत्रीकरण के लिए तुलना

यद्यपि तुलनाएँ हमारी सारी तर्क बुद्धि और चिंतन का अंतर्निहित हिस्सा हैं, वहीं अधिकांश तुलनावादी ये तर्क देंगे कि राजनीति का एक तुलनात्मक अध्ययन चेतनापूर्ण तुलनाएँ करने का प्रयास करता है ताकि ऐसे निष्कर्षों तक पहुँचा जा

सके जिनका सामान्यीकरण किया जा सकता है, अर्थात् अनेक मामलों के लिए ये सत्य हों। ऐसे सामान्यीकरणों को करने के लिए, राष्ट्रों के बारे में केवल सूचना एकत्रित करना पर्याप्त नहीं है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में सिद्धांत-निर्माण परीक्षण पर बल है जिसमें राष्ट्र इकाइयों या अध्ययन मामले के केस का काम करते हैं। अतः तुलनात्मक अनुसंधान कैसे किया जाना चाहिए, इस संबंध में नियमों और मानदंडों को विकसित करने पर काफी बल दिया जाता है और जोरदार प्रयास किए जाते हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन ये सुनिश्चित करता है कि सभी सामान्यीकरण एक से अधिक परिघटना के निरीक्षण या अनेक परिघटनाओं के बीच संबंधों के निरीक्षण पर आधरित है।

1.4.2 वैज्ञानिक कठोरता के लिए तुलनाएँ

जैसा कि अगली इकाई में व्याख्या की जाएगी, तुलनात्मक पद्धति इन सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार और कठोरता प्रदान करती है। जो सामाजिक वैज्ञानिक परिशुद्धता मान्यता और विश्वसनीयता पर बल देते हैं, वे सामाजिक विज्ञानों में तुलनाओं को अपरिहार्य मानते हैं क्योंकि ये सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन में 'नियंत्रण' का अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करते हैं। (सारटोरी, 1994)।

1.4.3 तुलनाएँ जो संबंधों में व्याख्याओं की ओर ले जाएँ

एक लम्बे समय तक तुलनात्मक राजनीति केवल समानताओं और भिन्नताओं को ढूँढती हुई नज़र आई और उसने इस प्रयास को राजनीतिक परिघटनाओं के वर्गीकरण, द्वि भागीकरण या ध्रुवीकरण की ओर निर्देशित किया। फिर भी, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण समानताओं और भिन्नताओं की पहचान करना मात्र नहीं है। अनेक विद्वानों का मानना है कि तुलनाओं का उद्देश्य "समानताओं और भिन्नताओं को पहचाने" या तथाकथित "तुलना और विषमता उपागम" से परे जाते हुए अंत में संबंधों के एक विस्तृत ढाँचें के अन्तर्गत राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना है। ऐसा माना जाता है कि ये हमारी समझ को गहन बनाने में मदद करेगा और राजनीतिक परिघटनाओं का उत्तर देने और व्याख्या करने के स्तरों का विस्तार करेगा। दूसरे शब्दों में, तुलनात्मक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल दूसरों के बारे में अविश्वासपूर्ण होना नहीं है बल्कि नए प्रमाण और तर्कों के प्रकाश में अपनी खुद की प्रणाली और धारणाओं से सवाल करना है।

बोध प्रश्न 3

नोट : i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) इकाई के अन्त में अपने उत्तर के लिए संकेतों को देखें।

1. आपके अनुसार राजनीति के एक तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है?

.....

.....

.....

.....

वे कौन सी विशेषताएँ हैं जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय-क्षेत्र का निर्धारण करते हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2. बीसवीं सदी में तुलनात्मक राजनीति के विकास की रुपरेखा का वर्णन प्रस्तुत करें जिसमें स्पष्ट करें (क) द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व और उसके पश्चात् की अवधि की विशिष्टताएँ (ख) विकासवाद और उसकी समालोचना (ग) बीसवीं सदी के उत्तरार्ध की गतिविधियाँ

.....

.....

.....

.....

.....

1.5 सारांश

राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति और विषयक्षेत्र का संबंध उसकी विषय -वस्तु, उसके अध्ययन क्षेत्र, जिस अनुकूल अवस्थिति से अध्ययन किया जाता है और जिस उद्देश्य की ओर अध्ययन निर्दिष्ट होता है, इन सब से है। परन्तु ये स्थिर नहीं रहे हैं और समय के साथ-साथ इनमें बदलाव आया है। जहाँ सबसे प्रारंभिक अध्ययनों की दिलचस्पी सरकारों और शासन व्यवस्थाओं के वर्गीकरण और निरीक्षण में थी, वहीं उन्नीसवीं सदी के अंत और बीसवीं सदी के प्रारंभ में तुलनात्मक राजनीति की दिलचस्पी पश्चिमी देशों की संस्थाओं की औपचारिक कानूनी संरचनाओं के अध्ययन मे थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त में विश्व मंच पर अनेक 'नए राष्ट्रों' का उदय हुआ जिन्होंने औपनिवेशिक प्रभुता से अपने को स्वतंत्र कर लिया था। उदारवाद के प्रभुत्व को साम्यवाद के उदय और विश्व मंच पर सोवियत संघ की सशक्त उपस्थिति द्वारा चुनौती दी गई। इस मोड़ पर तुलनावादियों के बीच सोच में बदलाव आया। वे अब उभरते हुए राजनीतिक व्यवहारों और प्रक्रियाओं की विविधता का अध्ययन करने लगे परन्तु, एक एकल व्यापक ढाँचे के अन्तर्गत। इसके साथ, 'प्रणालियाँ' और ' संरचनाएँ-कार्य' की अवधारणा का प्रचलन हुआ। इन ढाँचों का प्रयोग पश्चिमी विद्वानों, विशेष रुप से अमेरिका के विद्वानों द्वारा विकासवाद, आधुनिकीकरण इत्यादि जैसी एक ओर नवोदित राष्ट्रों के राजनीतिक अभिजनों को विकास, राष्ट्र-निर्माण और राज्य -निर्माण की अवधारणाएँ आकर्षक लगी, कई मामलों में उन्होंने अपने स्वयं के वैचारिक दृष्टिकोणों को विकसित किया और दोनों वैचारिक गुटों से निरपेक्ष रहने का निर्णय लिया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में 'प्रणाली' के एक व्यापक ढाँचे के अन्तर्गत, राजनीति का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन पर से

केन्द्रण हटने लगा और क्षेत्रीय प्रणालीगत अध्ययनों का महत्व बढ़ने लगा। इन अध्ययनों में राज्य पर केन्द्रण ने नागरिक समाज के भीतर शक्ति संरचनाओं और उसके राजनीतिक स्वरुपों के अध्ययन के पुनरुत्थान को सूचित किया, जिसे, तुलनात्मक राजनीति में प्रणालियों और संरचनाओं-कार्यों के आगमन से हानि पहुँची थी। इस दौर में, सोवियत संघ के विघटन ने उदारवाद और पूँजीवाद की विजय को चिन्हित करते हुए पश्चिमी विद्वानों को 'इतिहास का अंत' की घोषणा करने के लिए उत्तेजित किया। पूँजी का वैश्वीकरण, 1980 के दशक के उत्तरार्ध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो अब तक कायम है और विश्व के देशों के बीच अपने आपको तकनीकी, आर्थिक और सूचना अनुबंधों में अभिव्यक्त करता है, उसने तुलनावादियों को भी 'लोकतंत्र की ओर संक्रमण', 'वैश्विक बाज़ार' और 'नागरिक समाज' जैसी सार्वभौमवादी, समांगीकरणीय अभिव्यक्तियों को अपनाने के लिए प्रभावित किया है। ऐसी अभिव्यक्तियाँ हमें ये विश्वास दिलाना चाहती हैं कि वास्तव में कोई भिन्नताएँ, अनिश्चय और संघर्ष नहीं बचे हैं जिनकी तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से व्याख्या की आवश्यकता है। फिर भी परिघटनाओं को परखने का एक अन्य तरीका है और अनेक विद्वान नागरिक समाज के पुनरुत्थान को वैश्विक पूँजीवाद के लिए चुनौतियों की दृष्टि से देखते हैं जो विश्व भर में जन-आन्दोलनों और मज़दूर संघ सक्रियवाद से निकलते हैं।

1.6 मुख्य शब्द

नागरिक समाज : इस शब्द के विवादस्पद अर्थ हैं। कुल मिलाकर इसे एक देश के जीवन का हिस्सा माना जाता है जो न तो सरकार है और न ही अर्थव्यवस्था, बल्कि वह क्षेत्र है जिसके भीतर हित समूह, राजनीतिक दल और व्यक्ति, राजनीतिक रुप से उन्मुख तरीकों में एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

नियंत्रण : वैज्ञानिक अनुसंधान में नियंत्रण एक मानक व्यवस्था या स्थिति को उपलब्ध करने के लिए परीक्षण के दौरान नियमन और जाँचने की एक महत्वपूर्ण कार्यविधि या यंत्रावली है।

यूरोकेंद्रित : इसका संबंध उन पक्षपातपूर्ण (और विकृत) दृष्टिकोणों से है जो अन्य संस्कृतियों और समाजों पर यूरोपीय विचारों, मूल्यों, धारणाओं और सिद्धांतों के लागू किए जाने से प्रकट होते हैं।

प्रणालीविज्ञान : अनुसंधान के विभिन्न तरीकों का अध्ययन, जिसमें अनुसंधान प्रश्नों की पहचान, निश्चित घटनाओं और राजनीतिक परिणामों की व्याख्या के लिए सिद्धांतों का सूत्रीकरण, और अनुसंधान परिकल्पना का विकास भी शामिल है।

नव-उदारवाद : शास्त्रीय उदारवाद का एक उन्नत रुप जिसमें राजनीतिक अर्थव्यवस्था बाज़ारी व्यक्तिवाद और न्यूनतम राज्यनियंत्रणवाद पर संकेंद्रित होती है।

मानकीय : व्यवहार के मूल्यों और मानदंडों का निर्धारण जो 'क्या है' से नहीं बल्कि' क्या होना चाहिए' से संबंधित प्रश्नों पर विचार करना है।

सिद्धांत : एक सिद्धांत व्यवस्थित रुप से परस्पर संबंधित विचारों, रचनाओं या प्रस्तावों का एक समूह/सेट है जिसका अभिप्राय एक निश्चित परिघटना, घटनाओं या व्यवहार की व्यवस्थित व्याख्या करना है। सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारों, घटनाओं और परिघटनाओं के लिए व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।

1.7 संदर्भ

चिलकॉट, रॉनल्ड एच., 1994. "भाग 1 : परिचय", रॉनल्ड एच. चिलकॉट, थ्योरीज़ ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स : द सर्च फॉर ए पेराडाइम रीकंसिडर्ड, वेस्टव्यू प्रेस, बोल्डर, (द्वितीय संस्करण)

लैंडमैन, टॉड, 2000. इश्यूज़ एंड मेथड्स इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स : एन इंट्रोडक्शन, राउटलेज, लंदन.

लिम, टिमोथी सी., 2006 डूइंग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स : एन इंट्रोडक्शन टू एप्रोचस एंड इश्यूज़, बोल्डर, सीओ : लिन्न रिएन्नर.

मेर, पीटर, 1996. "कंपेरेटिव पॉलिटिक्स : एन आवरव्यू", आर.ई. गाडिनेंड एच. क्लिंगमैन (सं0), द न्यू हैंडबुक ऑफ पोलिटिकल साइन्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड.

मोहन्ती, मनोरंजन, 2000. 'मूविंग द सेंटर इन द स्टडी ऑफ पोलिटिकल थॉट एंड पोलिटिकल थ्योरी', मनोरंजन मोहन्ती, कंटेम्प्रेरी इंडियन पोलिटिकल थ्योरी, संस्कृति, नई दिल्ली

मोहन्ती, मनोरंजन, 1975" कंपेरेटिव पोलिटिकल थ्योरी एंड थर्ड वर्ल्ड सेंसिटिविटी", टीचिंग पॉलिटिक्स, नंम्बर्स. 1 एंड 2

सारटोरी, जियोवान्नी, 1994. "कम्पेर, व्हाई एंड हाऊ", मात्तेइ दोगन एंड अली कज़न्सिगिल (सं0), कम्पेरिंग नेशन्स, कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटजीज़, ब्लैकवेल, ऑक्सफोर्ड.

थेडा स्कोक्पॉल एंड एम. सॉमर्स, 1980. "द यूज़ ऑफ कंपेरेटिव हिस्ट्री इन मैक्रो सोशल इनक्वाइरी", कंपेरेटिव स्टडीज़ इन सोसाइटी एंड हिस्ट्री, ग्रंथ 22, अंक 2

वियार्ड, रॉवर्ड जे 1998. "इज कंपेरेटिव पॉलिटिक्स डेड. रीथिंकिंग द फील्ड इन द पोस्ट- कोल्ड वॉर ईरा", थर्ड वर्ल्ड क्वॉटर्ली, ग्रंथ 19, नं 0 5.

1.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) तुलनात्मक सरकार, व्यवस्थित तुलना के तरीकों के माध्यम से विभिन्न सरकारों का अध्ययन है। जबकि, तुलनात्मक राजनीति से विभिन्न सरकारों का पहलुओं का अध्ययन है, सरकारी और गैर-सरकारी भी। दूसरे शब्दों में, तुलनात्मक सरकार का विषय क्षेत्र सरकार के अध्ययन तक ही सीमित है, परन्तु तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की प्रकृति व्यापक है जिसका विस्तार राजनीतिक जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू तक है। अतः तुलनात्मक राजनीति का वर्णन अक्सर हर राजनीतिक वस्तु के अध्ययन के रुप में किया जाता है जिसमें राज्य, संस्थाएँ, व्यक्ति, समूह, राजनीतिक दल, हित समूह और सामाजिक आन्दोलन इत्यादि सम्मिलित हैं।

बोध प्रश्न 2

1) नहीं, ये मात्र सरकारों के अध्ययन की एक पद्धति नहीं है, ये कहीं अधिक व्यापक है। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र अपने में शासन, नीति सूत्रीकरणों, राजनीतिक प्रक्रिया, संस्थाओं और शासन प्रणालियों इत्यादि से जुडे मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को सम्मिलित करता है। ये हर राजनीतिक वस्तु का अध्ययन है जिसमें सभी प्रकार की राजनीतिक परिघटनाएँ शामिल हैं – सरकारी और गैर-सरकारी भी।

2) तुलनात्मक राजनीति के विषय-वस्तु, योजना और विषय क्षेत्र का विकास विभिन्न ऐतिहासिक युगों में, उस समय के बदलते हुए सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ के अनुसार होता रहा है। तुलनात्मक राजनीति के उद्‌भव और विकास को भौगोलिक स्थल के रुप में ही नहीं बल्कि विचारों और सिद्धांतों की दृष्टि से देखा जा सकता है। इतिहास के विभिन्न युगों के दौरान तुलनात्मक राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

बोध प्रश्न 3

1) राजनीति शास्त्र के अध्ययन में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन अनेक कारणों से उपयोगी है। तुलना के माध्यम से, दो या अधिक राजनीतिक प्रणालियों की विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं और परिघटनाओं के बीच भिन्नताओं और समानताओं की पहचान और व्याख्या की जा सकती है। ये दो या अधिक राजनीतिक प्रणालियों की विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं और परिघटनाओं के संबंध में हमारी समझ को गहन करने में भी मदद करती है। एक विस्तृत दृष्टिकोण से तुलनात्मक राजनीति, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के बारे में हमारी विवेकबुद्धि और सोच का हिस्सा है और सिद्धांतों के निर्माण, विभिन्न राजनीतिक मुद्दों, समस्याओं या परिघटनाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण में हमारी सहायता करती है।

2) राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रकृति और विषय -क्षेत्र का निर्धारण उसकी विशिष्ट विषय -वस्तु, भाषा, शब्दावली द्वारा होती है और उसके परिप्रेक्ष्यों का संबंध राजनीति शास्त्र के विषय से है जैसे लोकतंत्र, संस्थाएँ, चुनाव, संविधान, राजनीतिक दल, शक्ति का वितरण इत्यादि।

3) एक स्पष्ट-परिभाषित और व्यवस्थित अध्ययन के रुप में तुलनात्मक राजनीति की उत्पत्ति उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में हुई। परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व, यह अत्यधिक 'यूरोकेंद्रित' थी, अर्थात्, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्राँस इत्यादि जैसे यूरोपीय देशों के अध्ययन तक सीमित। परन्तु द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में नवोदित राज्यों की उत्पत्ति के साथ विद्वानों ने विश्व के अन्य भागों की राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन प्रारंभ किया। 1990 के दशक में वैश्वीकरण के कारण राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के विषय-क्षेत्र और ज्ञान-क्षेत्र में कमाल का विस्तार हुआ।